

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 6359/2024

अरबाज पुत्र श्री मीरबादशाह खान पठान, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी देवल्डी, पीएस
अरनोद, जिला प्रतापगढ़, राज.

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री चंदन सिंह जोधा
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	सुश्री सोनू मनावत, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

19/09/2024

1. याचिकाकर्ता यहां आपराधिक विविध में विद्वान विशेष न्यायाधीश, प्रतापगढ़ द्वारा पारित दिनांक 18.07.2024 के आदेश को चुनौती दे रहा है। मामला संख्या 103/2024 एफआईआर संख्या 131/2024 से संबंधित है, जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 और 22 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3 और 25 के तहत पुलिस स्टेशन अरनोद, जिला प्रतापगढ़ में दर्ज है। याचिकाकर्ता आरोपी द्वारा बीएनएसएस की धारा 94 और 348 के तहत सीसीटीवी फुटेज, कॉल लोकेशन और टावर लोकेशन की मांग करते हुए दायर आवेदन को आक्षेपित आदेश के तहत खारिज कर दिया गया।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 27.06.2024 को लगभग 4:15 बजे एसएचओ अरनोद को देवल्डी के बाहर एक फार्महाउस में एक व्यक्ति द्वारा अवैध एमडीएमए बेचने की सूचना मिली। शाम 5:00 बजे पहुंचने पर, पुलिस अधिकारियों ने याचिकाकर्ता यानी 19 वर्षीय अरबाज खान पठान को भागने की कोशिश करते

हुए पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से 545 ग्राम एमडीएमए और गोला-बारूद के साथ एक पिस्तौल बरामद हुई। वह किसी भी वस्तु का लाइसेंस नहीं दिखा सका, जिसके कारण पुलिस स्टेशन अरनोद में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

2.1 याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे झूठा फंसाया गया है और पुलिस कथित घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थी और यह सब एक मनगढ़ंत कहानी है। मुकदमे के दौरान, उसने बी.एन.एस.एस. की धारा 94 और 348 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें उसके दावों का समर्थन करने के लिए मोबाइल कॉल विवरण और सीसीटीवी फुटेज का अनुरोध किया गया। विद्वान विशेष न्यायालय ने 18.07.2024 के आदेश द्वारा इस आवेदन को खारिज कर दिया।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान सरकारी वकील को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि आक्षेपित आदेश घोर अवैधता से ग्रस्त है और स्थापित कानूनी सिद्धांतों के साथ-साथ अभियुक्तों के खुद का बचाव करने के मौलिक अधिकारों का खंडन करता है। याचिकाकर्ता को बिना किसी प्रतिबंधित सामान की बरामदगी के जबरन अरनोद पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसे झूठा फंसाया गया है। एसएचओ और उनकी टीम कथित घटना स्थल पर मौजूद नहीं थी। याचिकाकर्ता का भाई, एक आदतन अपराधी, वास्तव में जांच एजेंसी द्वारा पीछा किया जा रहा है, जिसने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए याचिकाकर्ता को झूठा फंसाने का सहारा लिया है।

5. कुछ इसी तरह की स्थिति में हाल ही में मुझे माला राम बनाम राजस्थान राज्य के मामले में एक और मामले से निपटने का अवसर मिला जिसमें सीसीटीवी फुटेज के बजाय, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कॉल विवरण को संरक्षित करने की मांग की गई थी। इसमें व्यक्त किए गए विचार, उपयुक्त होने के नाते, निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

7. उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि बीएनएसएस की धारा 94 को केवल न्यायालय या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के कहने पर ही लागू किया जा सकता है, जो किसी भी स्थिति में न्यायालय के लाभ के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी दस्तावेज पर विचार कर सकता है। इस प्रकार, अभियुक्त के लिए बीएनएसएस की धारा 94 को लागू करना खुला नहीं था। मेरा यह भी मानना है कि

तकनीकी रूप से, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने धारा 94 के तहत दायर आवेदन को खारिज करने में कोई अनियमितता नहीं की है।

8. हालांकि, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, मेरा यह विचार है कि न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, याचिका को योग्यता के आधार पर अनुमति दी जानी चाहिए।

9. बीएनएसएस की धारा 528 के तहत, इस न्यायालय के पास निहित शक्तियां हैं और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक आदेश देने का एक संगत कर्तव्य है।

10. यहां याचिकाकर्ता आईपीसी की धारा 302 के तहत गंभीर अपराध का आरोपी होने के कारण विचाराधीन है। यदि उसे दोषी ठहराया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप उसे मृत्युदंड और/या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साक्ष्य प्रस्तुत करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही से न्याय की विफलता होगी और अभियुक्त के बचाव को गंभीर रूप से जोखिम में डाला जा सकता है।

11. न्यायालय के प्रश्न पर, यह पता चला कि वर्तमान में अभियोजन पक्ष की गवाही ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की जा रही है। कार्यभार को देखते हुए, ऐसा हो सकता है कि बचाव पक्ष के साक्ष्य के चरण में, देरी के कारण, कॉल विवरण और स्थान विवरण, जिन्हें अभियुक्तों को अपने साक्ष्य में प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है, उस मोबाइल नेटवर्क के सेवा प्रदाता के डेटा बैंक से हटा दिए जाएं, जिसके अभियुक्त और अन्य गवाह ग्राहक हैं।

12. बीएनएसएस की धारा 95 का संदर्भ लिया जा सकता है, जो इस प्रकार है:-

"95. पत्रों के संबंध में प्रक्रिया-

(1) यदि डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज, पार्सल या वस्तु, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में इस संहिता के अंतर्गत किसी जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के लिए वांछित है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय डाक प्राधिकारी से दस्तावेज, पार्सल या वस्तु को ऐसे व्यक्ति को सौंपने की मांग कर सकता है, जिसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश दे।

(2) यदि ऐसा कोई दस्तावेज, पार्सल या वस्तु, किसी अन्य मजिस्ट्रेट, चाहे वह कार्यकारी हो या न्यायिक, या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसे किसी उद्देश्य के लिए वांछित है, तो वह डाक प्राधिकारी से ऐसे दस्तावेज, पार्सल या वस्तु की तलाशी लेने और उसे जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश तक रोके रखने की मांग कर सकता है। उपधारा (1) के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।”

13. धारा 95, सुप्रा, इस प्रकार न्यायालय को डाक अधिकारियों को ऐसे दस्तावेज या अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश देने की अनुमति देती है जो किसी लंबित मुकदमे के लिए प्रासंगिक हैं। यह धारा स्पष्ट रूप से न्यायालयों को ऐसे अभिलेखों के संरक्षण और उत्पादन का आदेश देने का अधिकार देती है, भले ही दस्तावेज अभियुक्त की हिरासत में हों या नहीं। धारा 95 के अनुसार, न्यायालय सेवा प्रदाताओं को बचाव चरण से पहले भी आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने और बनाए रखने का निर्देश दे सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये दस्तावेज आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हों। इस प्रकार यह प्रावधान समय बीतने के कारण बाद में उनके विलोपन से बचने के लिए अभिलेखों को सुरक्षित रखने की याचिकाकर्ताओं की दलील का समर्थन करता है।

13.1. मेरा विचार है कि आधुनिक समय के संदर्भ में, डाक प्राधिकरण को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि इसमें दूरसंचार प्राधिकरण भी शामिल हो जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में एक समान सेवा प्रदाता है जिसे वह अपने उपभोक्ताओं की ओर से संरक्षित करता है और वितरित करता है। तदनुसार, कोई भी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक डेटा या कोई वस्तु, जो अभियुक्त की अभिरक्षा में नहीं है, बल्कि तीसरे पक्ष, यानी डाक प्राधिकरण या टेलीग्राफ/दूरसंचार प्राधिकरण/सेवा प्रदाता के पास है, लेकिन साथ ही, यह लंबित मुकदमे के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, उसे साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

14. यदि बचाव पक्ष के साक्ष्य के चरण तक पहुंचने तक, कॉल विवरण और स्थान विवरण, जिन्हें अभियुक्तों को अपने साक्ष्य में प्रस्तुत करने

की सलाह दी गई है, मोबाइल नेटवर्क के सेवा प्रदाता के डेटा बैंक से पहले ही हटा दिए गए हैं, तो याचिकाकर्ता अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के मूल्यवान अवसर से वंचित हो जाएगा और इस प्रकार उसके बचाव में गंभीर रूप से पक्षपात होगा।

15. यह सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन प्रक्रिया न्याय की दासी है, इसलिए इसे न्याय को विफल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रक्रियात्मक नियम न्याय को सुविधाजनक बनाने के लिए मौजूद हैं, न कि इसे बाधित करने के लिए। यदि प्रक्रियात्मक नियमों का सख्ती से पालन करने से साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं और अभियुक्तों को अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं मिलता है, तो न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मानदंड से हट जाना चाहिए। न्यायालय को अपनी शक्तियों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए कि प्रक्रियात्मक देरी के परिणामस्वरूप अन्याय न हो। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को खोने से पहले संरक्षित करने की अनुमति देना प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता के लिए आवश्यक है।

16. इसके अलावा, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आपराधिक अभियोजन में अपना बचाव करने का अधिकार शामिल है। अभियुक्त को कॉल विवरण और स्थान रिकॉर्ड जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने की क्षमता से वंचित करना इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करे। इसी तरह, अभियुक्तों को साक्ष्य का विरोध करने और अपना बचाव प्रस्तुत करने का हर उचित अवसर दिया जाना चाहिए। कॉल और स्थान विवरण जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य को सुरक्षित रखने में विफलता अभियुक्त की बचाव करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करती है, जिससे निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा कमजोर होती है। न्याय की विफलता से बचने के लिए न्यायालयों का कर्तव्य है। प्रक्रियात्मक देरी के कारण महत्वपूर्ण साक्ष्य को खोने देने से भी अनुचित सुनवाई होगी, जिससे गलत दोषसिद्धि या कठोर सजा (इस मामले में आजीवन कारावास या

यहाँ तक कि मृत्युदंड भी शामिल है) हो सकती है। बचाव के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य (जो किसी तीसरे पक्ष के पास है) को सुरक्षित न करके, न्यायालय अनजाने में अभियोजन पक्ष के पक्ष में संतुलन बना देगा, जिससे असमानता पैदा होगी जिसे दूर किया जाना चाहिए।”

6. याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति और गिरफ्तारी के समय उसके स्थान को देखते हुए मेरा मानना है कि उसके द्वारा मांगी गई सीसीटीवी फुटेज एक प्रासंगिक साक्ष्य है। सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के आदेशों के अभाव में, आरोपी द्वारा जिस साक्ष्य पर भरोसा किया जाना है, वह समय बीतने के साथ डेटा रिकॉर्ड से मिट सकता है।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा उपलब्ध न होने से न्याय की विफलता हो सकती है, बशर्ते कि यह याचिकाकर्ता के अपने स्थान के संबंध में तथ्यात्मक दावे को साबित करे।

8. जो भी हो, यह तभी दावा किया जा सकता है जब उक्त सीसीटीवी फुटेज पेश की जाए।

9. तदनुसार, सीसीटीवी फुटेज की अनुपलब्धता से बचने के लिए, इसे सुरक्षित रखने के लिए आदेश पारित करना उचित समझा जाता है। अभियोजन पक्ष को संबंधित सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाता है।

10. परिणामस्वरूप, दिनांक 18.07.2024 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है तथा याचिकाकर्ता द्वारा विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष बी.एन.एस.एस. की धारा 94 के तहत दायर आवेदन को बी.एन.एस.एस. की धारा 95 के तहत विचारणीय माना जाता है तथा उसे स्वीकार किया जाता है।

11. वर्तमान विविध याचिका को उपरोक्तानुसार स्वीकार किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के

लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।